T.T. LIMITED
(CIN: L18101DL1978PLC009241)
879, Master Prithvi Nath Marg, Opp. Ajmal Khan Park, Karol Bagh, New Delhi, 110005,INDIA
0091 11 45060708 | 1800 1035 681 | newdelhi@ttlimited.co.in | www.ttlimited.co.in

TTL/SEC/2022-23
30th June, 2022

M/s National Stock Exchange of India Ltd." Exchange Plaza" **Plot No. C/1, G Block** **Bandra Kurla Complex** **Bandra (E), Mumbai-400051** **Ph.: 022-26598100-8114** **Scrip Code: TTL**	**Bombay Stock Exchange Limited** **Floor 35, P.J.Towers** **Dalal Street** **Mumbai-400001** **Fax-022-22722061/41/39/37** **Scrip Code : 514142**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI Listing Regulations, we enclose copies of advertisement published in newspapers viz. Open Search (English) and Open Search (Hindi) on 30th June, 2022 regarding 43rd Annual General Meeting and e-Voting information in respect of Resolutions contained in the Notice of 43rd Annual General Meeting of the Company to be held on 3rd August, 2022

The above information is also available on the website of the Company www.ttlimited.co.in

You are requested to take the above on record.

Thanking You,
Yours Sincerely
For TT Limited

For T.T. LIMITED
PANKAJ MISHRA
SECRETARY

Pankaj Mishra
Company Secretary & Compliance Officer

एक नज़र

हरियाणा प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल गठित : डॉ. विनोद कुमार शर्मा

ओपन सर्च. संवाददाता

हांसी। हरियाणा प्रेस क्लब द्वारा 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है। इन 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में से 5-5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा क्लब के प्रदेशाध्यक्ष मानसिंह वर्मा के नेतृत्व में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जुलाई के अन्तिम सप्ताह में हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की एक-एक प्रति भेंट की जाएगी। यह जानकारी देते हुए हरियाणा प्रेस क्लब के प्रदेश प्रवक्ता एवं चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में लिये गए सदस्यों में ताराचंद धनवाल (चंडीगढ़), अजय कुमार गुप्ता (चंडीगढ़), डॉ. विनोद कुमार शर्मा (चंडीगढ़), प्रकाशचंद्र शर्मा (चंडीगढ़), रविन्द्र कुमार तलवार (पंचकूला), देसराज भटनागर (कुरुक्षेत्र), राजेश डोगरा (अंबाला), पी. के. बंसल (जींद), डॉ. सतीश भारती (उकलाना मंडी), घनश्याम दास जिंदल (नारनौंद), हरकेश जांगड़ा (नारनौंद), हवा सिंह चहल (हांसी), मनमोहन शर्मा (हांसी), श विनोद कुमार खन्ना (आदमपुर मंडी), शेर सिंह गरीब (हिसार), पवन कुमार शर्मा (हिसार), राजबीर सिंह (हिसार), जयभगवान श्योराण (रोहतक), सोनिया सिंह (रोहतक) व रविन्द्र कुमार (कार्यालय सचिव) हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में 5-5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा प्रेस क्लब के प्रदेशाध्यक्ष मानसिंह वर्मा के नेतृत्व में शिमला व जयपुर जाएगा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की एक-एक प्रति दी जाएगी।

ड्रग इंस्पेक्टर बबलीन कौर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार, रिश्वत लेने के लगे हैं आरोप

अमृतसर (एजेंसी) गुरदासपुर व पठानकोट जिले की ड्रग इंस्पेक्टर बबलीन कौर को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर और विवरण जुटाया जा रहा है। मामले में कार्रवाई मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद की गई है। न्यू अमृतसर क्षेत्र में रहने वाली बबलीन कौर के घर पुलिस छापामारी करने पहुंची थी।

इस दौरान पुलिस ने घर में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। बताया जा रहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में छिपी हुई थीं। खबर मिलते ही पुलिस ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर बबलीन कौर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि, बबलीन कौर पर आरोप है कि उनके अधीनस्थ कार्यरत एक दर्जा चार कर्मचारियों ने मेडिकल स्टोर संचालक को लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। बताया जा रहा है कि दर्जा चार कर्मचारी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बबलीन का नाम लिया है। पुलिस बबलीन को कुछ देर बाद अमृतसर के सिविल अस्पताल लाएगी, जहां उनका मेडिकल करवाया जाएगा।

रेलवे के डीआरएम कार्यालय में सीबीआई की रेड, दो अधिकारी रिश्वत लेते चढ़े हत्थे

अंबाला (एजेंसी) इंडियन रेलवे सर्विस आफ सिग्नल इंजीनियर (आइआरएसएसई) विवेक और मुख्य कार्यालय अधीक्षक प्रवीण कुमार को सेंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन (सीबीआइ) ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। करीब बारह घंटे तक सीबीआइ की कार्रवाई चलती रही। अब दूसरे दिन भी सीबीआई जांच में जुटी है। पहले प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके बास विवेक कुमार को।

बिलों को पास करने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेने की बात सामने आई है। इस प्रकरण में सीबीआइ के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचे रहे। रात ग्यारह बजे तक सीबीआइ की टीम मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय में रही। आरोपित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपितों को बुधवार को पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। सीबीआइ को इसकी शिकायत की गई ,तो चंडीगढ़ की ब्रांच से एक टीम का गठन किया गया। बताते हैं कि काल रिकार्डिंग भी सीबीआइ को उपलब्ध करवाई गई, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आरोपित अधिकारियों को पकड़ने का जाल बिछाया गया।

लुधियाना में 1.70 लाख की नगदी सहित चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, कार की बैटरी बरामद

लुधियाना (एजेंसी) चोरी की वारदातें करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों की नगदी और कार की बैटरी बरामद की है। आरोपितों के खिलाफ दो केस दर्ज करके बुधवार को अदालत में पेश किया गया जहां से एक दिन का रिमांड हासिल करके कड़ी पूछताछ की जा रही है। थाना जमालपुर पुलिस ने हरियाणा से आकर चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एएसआइ राजकुमार ने बताया कि उनके कब्जे से चोरी के 1.70 लाख रुपये बरामद हुए।

आरोपितों की पहचान हिसार के हांसी निवासी काला तथा मंगल के रूप में हुई है। दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर मुंडियां के सुंदर नगर की 33 फुटा रोड पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 21 जून की रात दोनों आरोपितों ने मुंडियां इलाके में स्थित कोल्ड ड्रिंक की होलसेल दुकान गौरव ट्रेडिंग कंपनी के ताले तोड़ कर वहां से 1.70 लाख रुपये चोरी किए हैं। राजकुमार ने बताया कि उनका पुराना रिकार्ड चेक किया जा रहा है। उनसे की जा रही पूछताछ में अहम खुलासे होने की संभावना है।

नए स्टार्टअप का सहारा बनी हरियाणा सरकार, रिस्क फ्री रोजगार की गारंटी

चंडीगढ़ (एजेंसी)

हरियाणा में अब स्टार्ट अप को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ युवाओं की क्षमता का विकास होगा। हरियाणा सरकार राज्य में स्टार्ट अप का सहारा बनेगी और इससे जोखिम मुक्त रोजगार मिलेगा। हरियाणा में नए स्टार्टअप शुरू करने वालों पर वित्तीय प्रोत्साहन की बारिश हुई, हरियाणा सरकार की नई स्टार्टअप नीति युवाओं को अपना खुद का रोजगार खड़ा कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार के लिये तैयार करेगी। इस नीति के तहत राज्य में अगले पांच साल के भीतर कम से कम पांच हजार नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें करीब 75 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश में 3910 स्टार्टअप संचालित हैं, जबकि पूरे देश में इनकी संख्या 60 हजार के आसपास है। प्रदेश सरकार ने नए स्टार्टअप के लिये कई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उन्हें जोखिम फ्री बना दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और संचार विभाग द्वारा तैयार की गई स्टार्टअप पालिसी 2022 को मंजूरी दी गई थी।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई इसके पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि तक हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख लाभ लेने के लिए पात्र बन जाएंगे। शर्त यह रखी गई है कि उनका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। नई स्टार्टअप नीति पहले के आठ अलग-अलग कानूनों के बजाय 14 अलग-अलग कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति देकर स्टार्टअप को अधिक सुविधा प्रदान करेगी। इससे स्टार्टअप के लिए कारोबार करने में आसानी होगी। राज्य सरकार हर छह महीने में हरियाणा के 22 जिलों में विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगी, ताकि नई नीति के तहत स्टार्टअप विकास के अवसरों और क्षमता के बारे में जागरूक हो सकें। नई स्टार्टअप नीति के तहत यह मिलेंगे लाभ - नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति : सात वर्षों के लिए 50 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति। - लीज रेंटल सब्सिडी : स्टार्टअप के लिए पांच लाख रुपये तक लीज रेंटल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति। - स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग : 'ए' श्रेणी के ब्लाक में 100 स्टार्टअप, 'बी' श्रेणी के ब्लाक में 250 स्टार्टअप, 'सी' श्रेणी के ब्लाक में 750 स्टार्टअप और 'डी' में 1000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग मिलेगी। - पेटेंट लागत- स्टार्टअप को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पेटेंट पंजीकरण के लिए वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम 25 लाख रुपये होगी।

- क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति हरियाणा स्थित डेटा केंद्रों पर क्लाउड कंप्यूटिंग/स्टोरेज के लिए किए गए खर्च की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक होगी। - एक्सलरेशन कार्यक्रमों में सहायता- राष्ट्रीय एक्सलरेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपये और अंतर्राष्ट्रीय एक्सलरेशन कार्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इन्क्यूबेटरों को वित्तीय प्रोत्साहनः - पूंजीगत सब्सिडी- इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए गवर्नमेंट होस्ट इंस्टीट्यूट को दो करोड़ रुपये तक तथा निजी होस्ट इंस्टीट्यूट को एक करोड़ रुपये तक का पूंजी अनुदान दिया जाएगा। - सलाह सहायताः परामर्श सहायता के लिए सरकार के स्वामित्व /समर्थित/ प्रायोजित इन्क्यूबेटरों को 2.5 लाख रुपये तक प्रति इन्क्यूबेटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगी। - रेंटल चार्ज पर प्रतिपूर्ति : इनक्यूबेटर द्वारा लीज रेंट के रूप में किये गये भुगतान के लिए तीन साल की अवधि के लिए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। - स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रतिपूर्ति- भूमि/कार्यालय स्थान/आइटी भवन की खरीद/पट्टे पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी।

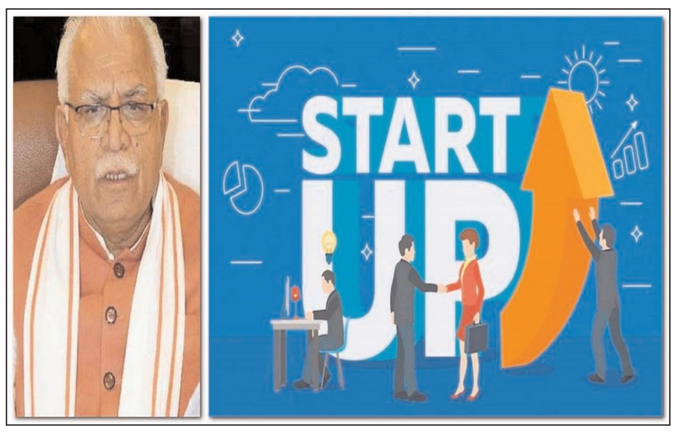

कपूरथला की 40 वर्षीय महिला में दिखे स्वाइन फ्लू के लक्षण, आइसीयू में किया गया आइसोलेट

जालंधर (एजेंसी) सिविल अस्पताल में इस साल का स्वाइन फ्लू का पहला संदिग्ध मरीज भर्ती किया गया है। कपूरथला के गांव कलोवाल की रहने वाली 40 वर्षीय महिला की तबियत खराब होने के बाद उसे यहां दाखिल किया गया। उसकी हालत गंभीर है और सैंपल लेकर पीजीआइ चंडीगढ़ भेज दिया गया है। सिविल सर्जन डा. रमन शर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू की दस्तक को लेकर विभाग ने सरकारी व निजी अस्पतालों के डाक्टरों को अलर्ट कर दिया है।

निजी अस्पताल में संदिग्ध स्वाइन फ्लू का मरीज आने पर तुरंत सेहत विभाग को सूचित करने की हिदायतें दी गई है। विभाग के पास स्वाइन फ्लू के मरीज का सैंपल लेने के लिए ट्यूबें, एन95 मास्क, दस्ताने तथा किटों का पर्याप्त स्टाक है। वहीं अस्पताल के डा. भूपिंदर सिंह ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। उसे ट्रामा सेंटर के आइसीयू में आइसोलेट किया गया है। सिविल अस्पताल में हर घातक बीमारी की दस्तक के बाद सेहत विभाग विशेष वार्ड बनाने की हिदायतें जारी कर रहा है।

अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आइसीयू बना हुआ है। वहीं मंकीपाक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया बै। डेंगू मरीजों के लिए भी विशेष वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में विशेष वार्डों की संख्या बढ़ रही है और ड्यूटी देने वाले स्टाफ की संख्या कम है। सिविल सर्जन डा. रमन शर्मा का कहना है कि कोरोना आइसीयू में ही दूसरे मरीजों से दूरी बनाते हुए स्वाइन फ्लू के मरीजों को दाखिल कर इलाज किया जा सकता है।

बाजवा ने फेंका प्रोटोकाल कमेटी बनाने का जाल,लेकिन नहीं फंसी आप सरकार

चंडीगढ़ (एजेंसी)

पंजाब विधानसभा में सबसे वरिष्ठ व अनुभवी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सदन में प्रोटोकाल कमेटी बनाने का जाल बनने की मांग की। बाजवा ने यह शून्यकाल के दौरान यह मांग तब उठाई जिस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब कैबिनेट में नंबर दो पर आने वाले वित्तमंत्री हरपाल चीमा नहीं थे। लेकिन सरकार ने उनकी मंशा भांप ली और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

बाजवा ने कहा, प्रोटोकाल के मुताबिक विधायकों का दर्जा मुख्य सचिव के बराबर है लेकिन विधायक अगर अधिकारियों को फोन करते है तो वह उठाते नहीं है। चिट्ठी लिखते है तो उसका जवाब नहीं देते। इसलिए सदन को एक प्रोटोकाल कमेटी बनानी चाहिए। अफसरों की कदमताल करवाना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, सरकार ने तुरंत भांपा बाजवा की मंशा को, बाजवा ने यह प्रस्ताव भी तब रखा जब स्पीकर कुलतार संधवा ने लुधियाना के बुड्ढ नाला की निगरानी के लिए हाउस की कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। बाजवा ने कहा, अफसरों में विधायकों के प्रति डर व खौफ तो होना चाहिए। लोक सभा में प्रोटोकाल कमेटी बनी हुई है। हरियाणा विधान सभा ने भी बनाई हुई है। इसलिए पंजाब विधान सभा को भी प्रोटोकाल कमेटी बनानी चाहिए। ट्रेजरी बैंच में बैठे पहली बार चुन कर आए विधायकों को बाजवा के प्रस्ताव की गहराई का अंदाजा नहीं था लेकिन छात्र राजनीति से सदन पहुंचे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बाजवा की मंशा को भांपने में देर नहीं लगाई। धालीवाल इस बात के विरोध में आ गए।

उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी समस्या नहीं है। जिस पर बाजवा ने कहा कि अफसरों की भी कदमताल करवानी चाहिए। यह सभी विधायकों के लिए है। इस पर धालीवाल ने कहा कि आप हाउस कि चिंता न करें। मंत्री को विरोध करते देख आप के विधायक भी विरोध में आ गए। बाजवा ने अपने प्रस्ताव पर थोड़ी देर तक तो स्टैंड किया लेकिन बाद में वह अपनी सीट पर बैठ गए। बता दें कि बतौर नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने अपने विधान सभा क्षेत्र में अफसरों की बैठक बुलाई थी। जिसमें अफसर नहीं गए थे। जिसकी शिकायत भी उन्होंने स्पीकर कुलतार संधावा से की थी। बाजवा चाहते थे कि अगर हाउस प्रोटोकाल कमेटी बना देती है तो उसके दायरे में सत्ताधारी ही नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक भी आ जाएंगे। ऐसे में अगर विधायक किसी अधिकारी को फोन करते है या चिट्ठी लिखते है और उसका जवाब नहीं आता है तो मामला प्रोटोकाल कमेटी में जा सकता है। इससे विपक्ष के विधायकों को भी सत्ता में कुछ हद तक 'बराबरी की पावर' मिल जाएगी। अहम पहलू यह है कि बाजवा ने सदन में जब यह प्रस्ताव रखा उस समय मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी अफसर गैलरी में मौजूद थे।

लुधियाना पीएयू के लिए एक साल से वाइस चांसलर नहीं ढूंढ पाई सरकार

लुधियाना (एजेंसी)

हरित क्रांति में अहम रोल अदा करने वाली और देश की अग्रणी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को पिछले एक साल से रेगुलर वाइस चांसलर नहीं मिल पाया है। 30 जून 2021 को पूर्व वीसी डा. बलदेव सिंह ढिल्लों का कार्यकाल खत्म हो गया था और वे इस पद से रिटायर हो गए थे। उनके बाद अब तक पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी के लिए योग्य वाइस चांसलर नहीं ढूंढ पाई है।

बता दें कि, रेगुलर वीसी पद भरने के लिए दो बार विज्ञापन निकाला गया। पहले 23 जुलाई 2021 में विज्ञापन जारी किया गया, उसके बाद नई सरकार के आने के बाद इस साल 5 अप्रैल को दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ। पहली बार जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब करीब 45 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार भी 60 से 70 के करीब लोगों ने अप्लाई किया। बताया जा रहा है कि दोनों बार स्क्रीनिंग भी हो गई। तब भी यूनिवर्सिटी को अब तक वाइस चांसलर नहीं मिल पाया है। कल वाइस चांसलर के पद को खाली हुए एक साल पूरे हो जाएंगे। पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी में आइएएस अफसरों को अस्थायी वीसी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। रेगुलर वाइस चांसलर की नियुक्ति न होने से पीएयू में रिसर्च के लिए फडिंग, नए अध्यापकों की नियुक्तियों से लेकर प्रमोशन तक प्रभावित हो रहे हैं। पीएयू के पूर्व वीसी डा. किरपाल सिंह औलख कहते हैं कि साल 1962 में यूनिवर्सिटी बनी थी। पहली बार हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में वीसी का पद एक साल से खाली है। बड़ी हैरानी की बात है कि देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शामिल पीएयू के लिए पिछले एक साल से पंजाब सरकार को योग्य वीसी नहीं मिल पा रहा है। पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल में वीसी लगाने में नाकाम रही, अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी वीसी की नियुक्ति को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। आइएएस आफिसर ही अस्थायी वीसी के तौर पर यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। वीसी के न होने की वजह से डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर एक्सटेंशन, कंप्ट्रोलर, डायरेक्टर रिचर्स व हैड की स्थायी पोस्टें नहीं भरी जा सकी। एडिशनल चार्ज पर ही यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी का साठ प्रतिशत बजट रिसर्च पर लगता है।

संगरूर उपचुनाव में बदलाव पर विधानसभा में भिड़े आप और कांग्रेस विधायक

कांग्रेस के विधायकों ने संगरूर में हुए बदलाव को लगकर आप पर तंज कसे

चंडीगढ़,(एजेंसी)

संगरूर लोकसभा उपचुनाव में हुए बदलाव पर पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों में भिड़ंत हो गई। उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को ने एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों पार्टियों के विधायकों का एक दूसरे के खिलाफ पारा चढ़ गया।

इसकी शुरूआत तब हुई जब खरड़ से आप की विधायक अनमोल गगन मान ने कहा कि बदलाव क्यों आया? अगर आपने (कांग्रेस) अच्छे काम किए होते तो आप का जन्म नहीं होता। अनमोल गगन मान यह तक कह दिया कि बजट पर टीका-टिप्पणी हो रही है, अगर पांच वर्ष में अगर वो नहीं किया जो 70 वर्ष में नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पलटवार करते हुए कहा कि संगरूर में भी आपने (अनमोल गगन मान) यही कहा था कि संगरूर में आम आदमी पार्टी हारी तो राजनीति छोड़ दूंगी।बजट बहस में हिस्सा लेते हुए अनमोल गगन मान ने कहा कि बदलाव क्यों आया, क्योंकि लोग आप लोगों (रिवायती पार्टियां) से थक चुके थे।

काम किया होता तो लोग नकारते नहीं। इस पर वड़िंग ने संगरूर में हुई आप सरकार की हार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आप चुनाव में संगरूर को अपनी राजधानी बता रही थी। लोगों ने तीन माह में ही आप को फारिग कर दिया। जिस पर सदन में खासा शोर-शराबा हुआ। शिक्षा मंत्री मीत हेयर ने कहा कि आप सरकार ने चुनाव में नई प्रथा डाली है। किसी को भी धमकी नहीं दी गई और न ही प्रशासन पर दबाव बनाया गया। जबकि इससे पूर्व हुए उपचुनाव में यह सब कुछ होता था। यही नहीं, आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि हारने और नकारने में अंतर होता है। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। अमन अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि 125 साल पुरानी पार्टी जमानत जब्त करवा कर भी खुश हो रही है। मीत हेयर के तंज का जवाब कांग्रेस विधायक डा. राजकुमार चब्बेवाल ने भी आप पर तंज कसते हुए दिया। उन्होंने कहा कि क्रांति की शुरूआत संगरूर से हो चुकी है, जड़ तो कट गई है। बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि सपने ऐसे दिखाए गए जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो। उन्होंने कहा, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा-ए खून न निकला।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर से लगातार दो बार सांसद रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत मान आप के एक मात्र सांसद चुने गए थे। संगरूर सीट भगवंत मान के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई थी और कुछ दिन पहले हुए उपचुनाव में आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह को हार का सामना करना पड़ा था।

T T LIMITED
(CIN NO.-L18101DL1978PLC009241)
879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi – 110005
Website: www.ttlimited.co.in; Email: newdelhi@tttlimited.co.in;
TEL: +91-11-45060708

NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The 43rd AGM will be held on Wednesday, 3rd August, 2022 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April, 5th May 2020, and 05th May, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated 15 January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), and without the physical presence of the Members at a common venue.
   In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 43rd AGM and Annual Report 2021-22 including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2022 ("Annual Report 2021-22") has been sent to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of 43rd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including 43rd AGM Notice is also available on the Company's website at **www.ttlimited.co.in**, website of the Bombay Stock Exchange at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange at **www.nseindia.com** respectively. The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.
2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 27th July 2022 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of 43rd AGM electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are informed that:
   (i) the /Ordinary/ Special Business, as set out in the Notice of 43rd AGM, will be transacted through voting by electronic means;
   (ii) the remote e-Voting shall commence on Saturday, 30th July, 2022 at 9:00 A.M. IST;
   (iii) the remote e-Voting shall end on Tuesday, 02nd August, 2022 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05.00 p.m. IST.
   (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 43rd AGM, is 27th July, 2022;
   (v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of 43rd AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 27th July 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
   (vi) In case of any queries or issues regarding attending AGM / e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section.
   (vii) those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with Company, by email to Company email id: investors@ttlimited.co.in, Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
3. Pursuant to section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 28th July 2022 to Wednesday, 3rd August 2022 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
For TT Limited
Sd/-
Pankaj Mishra
Company Secretary
(Membership No A40550)

Place: New Delhi
Date: 30.06.2022

Philippine News Website, Co-founded By Nobel Laureate, Ordered To Shut Down

MANILA: (AGENCY)

A Philippine news site co-founded by Nobel Peace Prize winner Maria Ressa has been ordered to shut down, the company said Wednesday, a day before President Rodrigo Duterte -- its arch-nemesis -- leaves office.

Ressa has been a vocal critic of Duterte and the deadly drug war he launched in 2016, triggering what media advocates say is a grinding series of criminal charges, probes and online attacks against her and Rappler. The latest blow was delivered by the Philippine Securities and Exchange Commission. In a statement Wednesday, it confirmed the "revocation of the certificates of incorporation" of Rappler for violating "constitutional and statutory restrictions on foreign ownership in mass media". Rappler said the decision "effectively confirmed the shutdown" of the company and vowed to appeal,

describing the proceedings as "highly irregular". "We have discussed all possible scenarios with Rapplers (staff) since SEC issued its first order in 2018," Glenda Gloria, executive editor and co-founder of the site, told reporters. "Nothing ever sufficiently prepares an organization for a 'kill' order." Rappler has had to fight for survival as Duterte's government accused it of violating a constitutional ban on foreign ownership in securing funding, as well as tax evasion. It has also been accused of cyber libel -- a new criminal law introduced in 2012, the same year Rappler was founded.

Duterte has attacked the website by name, calling it a "fake news outlet", over a story about one of his closest aides. The news portal is accused of allowing foreigners to take control of its website through its parent Rappler Holdings' issuance of "depositary receipts". Under the constitution, investment in media is reserved for Filipinos or Filipino-controlled entities.

The case springs from the 2015 investment from the US-based Omidyar Network, which was established by eBay founder Pierre Omidyar. Omidyar later transferred its investment in Rappler to the site's local managers to stave off efforts by Duterte to shut it down.

Ressa, who is also a US citizen, and Russian journalist Dmitry Muratov were awarded the Nobel Peace Prize in October for their efforts to "safeguard freedom of expression".

Ressa is fighting at least seven court cases, including an appeal against a conviction in a cyber libel case, for which she is on bail and faces up to six years in prison. The International Center for Journalists has urged the Philippine government to reverse its order to shut down Rappler. "This legal harassment not only costs Rappler time, money and energy. It enables relentless and prolific online violence designed to chill independent reporting," ICFJ said in a statement posted on Twitter. Ferdinand Marcos Jr, the son of the Philippines' former dictator who presided over widespread human rights abuses.

Russia, China Eye NATO's 'Arctic Achilles Heel', Born Of Strange Treaties

NORWAY: (AGENCY)

Russian flags flap in the stiff polar breeze, a bust of Lenin looms out of the snow and a vast slogan declares, "Communism is our goal!"

No, this is not some time warp Soviet settlement lost in the Arctic wastes, but a corner of Norway where Moscow can -- theoretically at least -- mine, build, drill and fish what it likes. Welcome to Spitsbergen, the largest island of the Svalbard archipelago and "NATO's Achilles heel in the Arctic".

These spectacular islands of glaciers and mountain peaks halfway between Norway and the North Pole are a strategic and economic bridgehead not just for Moscow but also for Beijing.

All because of one of the most bizarre and little-understood international treaties ever concluded, which gives Norway sovereignty but allows the citizens of 46 countries to exploit the islands' potentially vast resources on an equal footing. Which is why 370 Russians and Ukrainian miners from the Donbass work in Barentsburg, a cut-off corner of Spitsbergen where the Soviets dug coal for decades and where it is pitch dark for nearly three months of the year. archipelago which has been a haunt of its hunters, whalers, fishermen since the 16th century. It also insists on calling the islands by the original Spitsbergen rather than the Norwegian Svalbard, the official name

"Spitsbergen has been covered with Russian sweat and blood for centuries," Moscow's consul Sergey Gushchin said.

"I'm not arguing that it's not Norwegian territory but it's part of Russian history," he added. He makes no attempt to hide that some Ukrainians have left since the Russian invasion in February. Moscow has long wanted a bigger say in the since shortly after the treaty handing them to Norway was signed in 1920 while Russia was otherwise engaged with the civil war between Reds and Whites. Nuclear submarines from Russia's powerful Northern Fleet also have to pass close to Svalbard's southernmost Bear Island to get into the North Atlantic. Russia's "main interest is to avoid a situation.

G7 Talks With India, China On Russian Oil Price Cap Positive: Report

WASHINGTON: (AGENCY)

Group of Seven democracies have had positive and productive discussions with China and India about a plan to cap the price of Russian oil, a source familiar with the G7 discussions said on Tuesday, adding the two major oil consumers would have incentives to comply.

The source, speaking on condition of anonymity, said the price-per-barrel cap level had not yet been determined, but it would have to be high enough to give Russia an incentive to keep producing oil.

Russian crude has been selling at heavy discounts of $30 to $40 per barrel compared to benchmark Brent crude prices of $110 to $120 per barrel due to Western sanctions on Moscow over its invasion of Ukraine.

G7 leaders on Tuesday agreed to explore imposing a ban on transporting Russian oil that has been sold above a certain price in an effort to reduce Moscow's revenues and deplete its war chest.

With the European Union preparing to impose a phased embargo on Russian oil later this year, US Treasury Secretary Janet Yellen has advocated the cap as a way to cut Russia's oil revenues while keeping supplies on the market and avoiding another major price spike that could prompt a recession.

The source said G7 governments were still determining which services for oil transport could be withdrawn for cargoes above the price cap and were considering direct bans of shipping services, insurance, trade finance, brokering of cargoes and other services.

Western sanctions still allow many countries to buy Russian crude, and India and China have increased their purchases at steep discounts. The source said the two countries would be able to buy Russian crude at even lower prices under the plan, calling it an attractive pitch to Beijing and New Delhi.

If Russia were simply to refuse to sell its crude at the capped price, it would have few options to sell it at higher prices, given the limited number of ships that would be available for subverting the sanctions that are outside of London-based insurance and financing markets, the source said.

With limited storage capacity, Russia would then have to significantly shut down production, reducing its cash flow and causing further damage to its energy sector, the source added.

Israel Heads Towards Snap Election, Yair Lapid Set To Be PM

JERUSALEM: (AGENCY)

Israel's parliament is expected to dissolve Wednesday, ending Prime Minister Naftali Bennett's year-long tenure and triggering a fifth election in less than four years that could see ex-premier Benjamin Netanyahu reclaim power. Barring an 11th hour shock agreement to save the coalition or form a new government within the existing parliament, Bennett's eight-party alliance is due to end by midnight, installing Foreign Minister Yair Lapid as prime minister.

The former television anchor is set to head a caretaker government, ahead of polls due in late October or early November. Bennett's motley alliance formed in 2021 offered a reprieve from an unprecedented era of political gridlock, ending Netanyahu's record 12 consecutive years in power and passing Israel's first state budget since 2018.

Netanyahu -- a divisive hawk aligned with far-right nationalists and Israel's ultra-Orthodox Jewish parties -- has promised victory in new elections but may again struggle to rally a parliamentary majority, multiple polls have shown.

He is currently on trial over corruption charges, which he denies. The anti-Netanyahu camp will likely be led by Lapid, a centrist former TV celebrity. Dismissed as a lightweight when he entered politics a decade ago, he has surprised many with his political skills.

As he and Bennett announced last week that their coalition was no longer tenable, Lapid sought to cast Netanyahu's potential return to office as a national threat.

"What we need to do today is go back to the concept of Israeli unity. Not to let dark forces tear us apart from within," Lapid said. While parliament's collapse appeared a near certainty, last-minute surprises remained possible given Israel's volatile political climate.

Factions across the political spectrum fear fresh polls will see them lose seats or end up out of parliament entirely by falling below the minimum support threshold, which is 3.25 percent of all votes cast.

But options to avoid another election were growing increasingly remote, according to Israeli reports.

That means Lapid is expected to take office at midnight after parliament gives final approval to a dissolution bill, in accordance with the power-sharing deal he agreed with Bennett last June.

Bennett, a religious nationalist, has led a coalition of right-wingers, centrists, doves and Islamists from the Raam faction, which made history by becoming the first Arab party to support an Israeli government in the Jewish state's 74-year history. The alliance, united by its desire to oust Netanyahu and break a damaging cycle of inconclusive elections, was imperilled from the outset by its ideological divides.

But Bennett said the final straw was a failure to renew a measure that ensures the roughly 475,000 Jewish settlers in the occupied West Bank live under Israeli law.

Some Arab lawmakers in the coalition refused to back a bill they said marked a de facto endorsement of a 55-year occupation that has forced West Bank Palestinians to live under Israeli rule.

For Bennett, a staunch supporter of settlements, allowing the so-called West Bank law to expire was intolerable. Dissolving parliament before its June 30 expiration temporarily renews the measure.

"We fought like lions, down to the very last moment, until it simply became impossible," Bennett told Israel's Channel 12 days after announcing his coalition's demise.

Bennett is expected to stay on as alternate prime minister and be responsible for Iran policy, as world powers take steps to revive stalled talks on Tehran's nuclear programme.

Israel opposes a restoration of the 2015 agreement that gave Iran sanctions relief in exchange for checks on its nuclear programme. Lapid will retain his foreign minister title while serving as Israel's 14th premier.

Briefs News

Biden Announces US Military Air, Sea, Land Reinforcements In Europe

MADRID: (AGENCY)

President Joe Biden on Wednesday announced US reinforcements of NATO forces in Europe, saying the alliance is needed more today "than it ever has been." NATO will be "strengthened in all directions across every domain - - land, air and sea," he said at a summit of the transatlantic alliance being held in Madrid. Biden, who was meeting with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, said the extra forces included: Boosting the fleet of US naval destroyers from four to six in Rota, Spain. A permanent headquarters in Poland of the 5th Army Corps. An "additional rotational brigade" in Romania, consisting of "3,000 fighters and another 2,000 personnel combat team." Enhanced rotational deployments in the Baltic countries. Two additional squadrons of the F-35 stealth plane to Britain. "Additional air defence and other capabilities in Germany and in Italy."

"Together with our allies we're going to make sure that NATO is ready to meet the threats from all directions across every domain," Biden said.

"In a moment where (Russian President Vladimir) Putin has shattered peace in Europe and attacked the very, very tenets of rule-based order, the United States and our allies, we're going to step up," he said.

US Opens Probe As 51 Migrants Die In Sweltering Truck

SAN ANTONIO: (AGENCY)

The death count of undocumented migrants who were abandoned in a scorching-hot trailer in Texas rose to 51 Tuesday, as President Joe Biden blamed "criminal" professional smugglers for the tragedy. Rebecca Clay-Flores, a Bexar County official, reported the new tally of "39 men and 12 women" dead, following the Monday discovery of the tractor-trailer on an isolated road in her district.

She did not say how many survivors remained in hospital, but the number could be around 11 based on initial figures that officials gave, including possibly four children. The Department of Homeland Security announced it had opened a criminal investigation, as Biden took aim at human smuggling gangs. "The tragic loss of life in San Antonio, Texas that took place yesterday is horrifying and heartbreaking," he

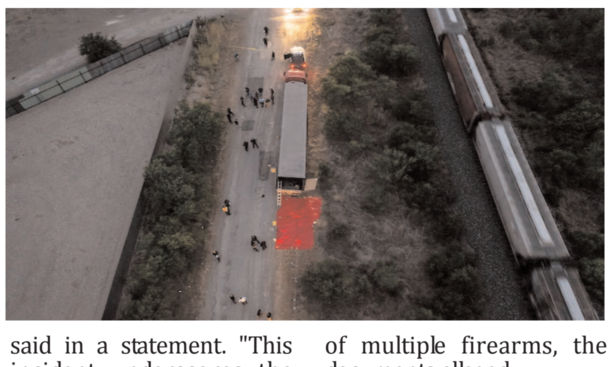

said in a statement. "This incident underscores the need to go after the multi-billion dollar criminal smuggling industry preying on migrants and leading to far too many innocent deaths," he said. Intense heat Federal law enforcement agents on Tuesday arrested two men at the address linked to the tractor-trailer's registration, court documents showed.

Juan Francisco D'Luna-Bilbao and Juan Claudio D'Luna-Mendez, both Mexican nationals whose US tourist visas had expired, were illegally in possession of multiple firearms, the documents alleged.

A third person, suspected of being the driver of the tractor-trailer, was arrested nearby while "very high on meth," reported the local daily San Antonio Express-News, citing a law enforcement officer. According to Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador, of the dead whose identities are known, 22 were from Mexico, seven from Guatemala and two from Honduras. "It's a tremendous misfortune," he told reporters. It was the deadliest single incident involving migrants along the southern border in memory, and drew more attention to the risks that hundreds of thousands of people face seeking to enter the United States from Mexico without permission. On Monday, the high temperature in San Antonio was 103 degrees Fahrenheit (39.4 degrees Celsius).

CENTRAL ORGANISATION FOR RAILWAY ELECTRIFICATION
1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj-211001, Fax No. 0532-2407892,
www.core.indianrailways.gov.in

No. RE/Tender/Civil/515 Date : 29.06.2022

E-TENDER NOTICE

Name of Work: Manpower outsourcing services viz. mason, Carpenter, Plumber, Painter, Welder, Majdoor/Labour for rendering annual services of maintenance of CORE service building and Staff Quarters at various locations of CORE at Prayagraj for one year.

1	**Completion Period :** 12 Months
2	**Approximate Cost of the work :** ₹ 43,83,862.37
3	**Tender Cost :** ₹ 0.00
4	**Earnest money to be deposited :** ₹ 87,677.00
5	**GeM Bid Document No. :** GEM/2022/B/2299952 Dated: 28.06.2022
6	**Submission/Opening of tender :** 21.07.2022 Upto 15:00 Hours for submission of tender through www.gem.gov.in and the Tender shall be opened online using GeM portal any time after closing of tender.
7	**Website particulars :** www.gem.gov.in (Please refer this site for details of E tender.).
8	**Office address :** Office of PCE/CORE, 1 Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj.

Note: Only e-Bid shall be accepted against above tender.

No. PR/164/2022
R.D. Adv

Dy.Chief Engineer,CORE/Prayagraj
FOR & ON BEHALF OF PRESIDENT OF INDIA

"Serving Customers with a Smile"

T T LIMITED
(CIN NO.-L18101DL1978PLC009241)
879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi – 110005
Website: www.ttlimited.co.in; Email: newdelhi@tttlimited.co.in;
TEL: +91-11-45060708

NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The 43rd AGM will be held on Wednesday, 3rd August, 2022 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April, 5th May 2020, and 05th May, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated 15 January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), and without the physical presence of the Members at a common venue.
   In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 43rd AGM and Annual Report 2021-22 including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2022 ("Annual Report 2021-22") has been sent to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of 43rd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including 43rd AGM Notice is also available on the Company's website at www.ttlimited.co.in, website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and National Stock Exchange at www.nseindia.com respectively. The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.
2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 27th July 2022 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of 43rd AGM electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are informed that:
   (i) the /Ordinary/ Special Business, as set out in the Notice of 43rd AGM, will be transacted through voting by electronic means;
   (ii) the remote e-Voting shall commence on Saturday, 30th July, 2022 at 9:00 A.M. IST;
   (iii) the remote e-Voting shall end on Tuesday, 02nd August, 2022 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05.00 p.m. IST.
   (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 43rd AGM, is 27th July, 2022;
   (v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of 43rd AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 27th July 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
   (vi) In case of any queries or issues regarding attending AGM / e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section.
   (vii) those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with Company, by email to Company email id: investors@ttlimited.co.in, Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
3. Pursuant to section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 28th July 2022 to Wednesday, 3rd August 2022 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
For TT Limited
Sd/-
Pankaj Mishra
Company Secretary
(Membership No A40550)

Place: New Delhi
Date: 30.06.2022